हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2018

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2018

खण्डों का क्रम

खण्ड :

1. संक्षिप्त नाम ।

2. हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए ₹ 33,27,47,34,196 की और राशि जारी करना ।

3. विनियोग ।

अनुसूची।

हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2018

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से सेवाओं के लिए कतिपय और धनराशियों के संदाय को प्राधिकृत करने और उनका विनियोग करने के लिए **विधेयक।**

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम, 2018 है । संक्षिप्त नाम ।

2. हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से **अनुसूची** के तृतीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट से अनधिक धनराशियां, जिनका योग केवल ₹ 33,27,47,34,196 (तीन हजार तीन सौ सत्ताईस करोड़, सैंतालीस लाख चौंतीस हजार एक सौ छियानवे रुपए) हैं, संदत्त और उपयोजित की जाए, जिनका वित्तीय वर्ष 2017 - 2018 की अवधि में **अनुसूची** के द्वितीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों से सम्बन्धित विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिए उपयोग किया जाएगा । हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए ₹33,27,47,34,196 की और राशि जारी करना ।

3. इस अधिनियम द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य की सचित निधि में से संदत्त और उपयोजित किए जाने के लिए प्राधिकृत धनराशियों का इस अधिनियम की धारा 2 के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि से सम्बन्धित **अनुसूची** में अभिव्यक्त सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजन किया जाएगा। विनियोग ।

अनुसूची

(धारा 2 और 3 देखें)

मांग संख्या	सेवाएं और प्रयोजन		निम्नलिखित राशियों से अनधिक		
			विधान सभा द्वारा दत्तमत ₹ में	संचित निधि पर प्रभारित ₹ में	कुल ₹ में
1	2		3	4	5
1	विधान सभा	(राजस्व)	4,21,94,086	21,66,000	4,43,60,086
		(पूंजीगत)	30,00,000	—	30,00,000
2	राज्यपाल और मन्त्री परिषद्	(राजस्व)	2,70,10,000	88,96,000	3,59,06,000
3	न्याय प्रशासन	(राजस्व)	15,98,53,203	2,61,45,000	18,59,98,203
		(पूंजीगत)	12,99,98,000	—	12,99,98,000
4	सामान्य प्रशासन	(राजस्व)	19,52,85,900	2,51,73,000	22,04,58,900
		(पूंजीगत)	1,84,17,000	—	1,84,17,000
5	भू-राजस्व व जिला प्रशासन	(राजस्व)	1,06,02,67,000	2,44,000	1,06,05,11,000
6	आबकारी और कराधान	(राजस्व)	9,23,25,000	—	9,23,25,000
7	पुलिस और सम्बद्ध संगठन	(राजस्व)	91,33,39,868	7,79,517	91,41,19,385
		(पूंजीगत)	68,03,000	—	68,03,000
8	शिक्षा	(राजस्व)	2,79,57,66,277	—	2,79,57,66,277
		(पूंजीगत)	94,57,03,000	—	94,57,03,000
9	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	(राजस्व)	1,62,29,78,500	4,96,284	1,62,34,74,784
		(पूंजीगत)	1,25,62,01,000	—	1,25,62,01,000
10	लोक निर्माण-सड़क, पुल तथा भवन	(राजस्व)	1,55,70,32,000	7,94,585	1,55,78,26,585
		(पूंजीगत)	1,35,41,63,000	18,14,26,586	1,53,55,89,586
11	कृषि	(राजस्व)	31,72,14,296	—	31,72,14,296
12	उद्यान	(राजस्व)	46,26,72,828	—	46,26,72,828
		(पूंजीगत)	12,00,00,000	—	12,00,00,000

1	2		3	4	5
13	सिंचाई, जलापूर्ति एवं सफाई	(राजस्व)	1,77,80,67,515	—	1,77,80,67,515
		(पूंजीगत)	77,94,52,000	—	77,94,52,000
14	पशु पालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य	(राजस्व)	20,000	—	20,000
		(पूंजीगत)	39,98,000	—	39,98,000
15	योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना	(राजस्व)	21,85,87,000	—	21,85,87,000
		(पूंजीगत)	66,47,50,000	—	66,47,50,000
16	वन और वन्य जीवन	(राजस्व)	18,81,96,000	21,83,741	19,03,79,741
		(पूंजीगत)	33,15,000	—	33,15,000
17	निर्वाचन	(राजस्व)	23,86,58,752	—	23,86,58,752
18	उद्योग, खनिज, आपूर्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी	(राजस्व)	2,44,39,810	—	2,44,39,810
		(पूंजीगत)	44,45,000	—	44,45,000
19	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	(राजस्व)	1,00,87,02,493	—	1,00,87,02,493
		(पूंजीगत)	1,00,00,000	—	1,00,00,000
20	ग्रामीण विकास	(राजस्व)	31,88,14,000	24,41,000	32,12,55,000
		(पूंजीगत)	26,17,000	—	26,17,000
21	सहकारिता	(राजस्व)	1,94,45,239	—	1,94,45,239
		(पूंजीगत)	56,32,51,200	—	56,32,51,200
22	खाद्य और नागरिक आपूर्ति	(राजस्व)	55,15,29,983	—	55,15,29,983
23	विद्युत विकास	(राजस्व)	2,72,31,628	—	2,72,31,628
		(पूंजीगत)	2,29,85,28,000	—	2,29,85,28,000
24	मुद्रण एवं लेखन सामग्री	(राजस्व)	5,22,92,974	—	5,22,92,974
25	सड़क और जल परिवहन	(राजस्व)	91,17,72,753	—	91,17,72,753
		(पूंजीगत)	5,90,00,000	—	5,90,00,000
26	पर्यटन और नागर विमानन	(राजस्व)	50,21,39,500	—	50,21,39,500
		(पूंजीगत)	1,55,79,000	—	1,55,79,000

1	2		3	4	5
27	श्रम, रोजगार और प्रशिक्षण	(राजस्व)	9,29,17,516	—	9,29,17,516
		(पूंजीगत)	2,65,00,000	—	2,65,00,000
28	शहरी विकास, नगर एवं	(राजस्व)	15,10,54,000	—	15,10,54,000
	ग्राम योजना तथा आवास	(पूंजीगत)	7,50,00,000	—	7,50,00,000
29	वित्त	(राजस्व)	33,62,91,817	3,17,42,38,000	3,51,05,29,817
		(पूंजीगत)	3,000	3,95,28,60,000	3,95,28,63,000
30	विविध सामान्य सेवाएं	(राजस्व)	18,38,91,000	2,53,61,334	20,92,52,334
		(पूंजीगत)	4,71,41,000	—	4,71,41,000
31	जनजातीय विकास	(राजस्व)	41,50,68,900	45,12,000	41,95,80,900
		(पूंजीगत)	38,89,03,000	—	38,89,03,000
32	अनुसूचित जाति	(राजस्व)	33,82,33,111	—	33,82,33,111
	उप-योजना	(पूंजीगत)	48,69,57,000	—	48,69,57,000
		(राजस्व)	**16,60,32,92,949**	**3,27,34,30,461**	**19,87,67,23,410**
	जोड़	**(पूंजीगत)**	**9,26,37,24,200**	**4,13,42,86,586**	**13,39,80,10,786**
		कुल जोड़	**25,86,70,17,149**	**7,40,77,17,047**	**33,27,47,34,196**

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक, भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के साथ पठित अनुच्छेद 204 के खण्ड (1) के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के अनुमानित व्ययों के सम्बन्ध में संचित निधि पर प्रभारित व्ययों और विधान सभा द्वारा यथा दत्तमत अन्य व्ययों को पूरा करने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की सचित निधि में से अपेक्षित और धन के विनियोजन का उपबन्ध करने के लिए पुरःस्थापित है ।

(जय राम ठाकुर)
मुख्य मन्त्री ।

शिमला :
तारीख 7 मार्च, 2018

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें

(वित्त विभाग नस्ति संख्या: फिन-ए.सी. (6)2/2017)

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2018 की विषय-वस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात्, भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन उक्त विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करते हैं ।

हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2018

31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से सेवाओं के लिए कतिपय और धनराशियों के संदाय को प्राधिकृत करने और उनका विनियोग करने के लिये **विधेयक**।

(जय राम ठाकुर)
मुख्य मन्त्री ।

(यशवन्त सिंह चोगल)
सचिव (विधि) ।

शिमला :
तारीख 7 मार्च, 2018

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

BILL NO. 1 OF 2018

THE HIMACHAL PRADESH APPROPRIATION BILL, 2018

(As Introduced in the Legislative Assembly)

THE HIMACHAL PRADESH APPROPRIATION BILL, 2018

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses :

1. Short title.

2. Issue of a further sum of ₹ 33,27,47,34,196 out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh for the financial year 2017-2018.

3. Appropriation.

THE SCHEDULE.

Bill No. 1 of 2018

THE HIMACHAL PRADESH APPROPRIATION BILL, 2018

(As Introduced in the Legislative Assembly)

A

BILL

to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh for the services for the financial year ending onthe 31st day of March, 2018.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-ninth Year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Appropriation Act, 2018. Short title.

2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh, there may be paid and applied sums not exceeding those specified in column (3) of the SCHEDULE amounting in the aggregate to a sum of ₹ 33,27,47,34,196 (Rupees Three Thousand Three Hundred Twenty Seven crores, Forty Seven Lakh, Thirty Four Thousand One Hundred Ninety Six only) towards defraying the several charges which will come in course of payment during the financial year 2017-2018 in respect of the services and purposes specified in column (2) of the SCHEDULE. Issue of a further sum of ₹ 33,27,47,34,196 out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh for the financial year 2017-2018.

3. The sums authorized to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh by this Act shall be further appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the period specified under section 2 of this Act. Appropriation.

THE SCHEDULE

(*See* sections 2 and 3)

Demand No.	Services and purposes		Sums not exceeding		
			Voted by the Legislative Assembly in ₹	Charged on the Consolidated Fund in ₹	Total in ₹
1	2		3	4	5
1	Vidhan Sabha	(Revenue)	4,21,94,086	21,66,000	4,43,60,086
		(Capital)	30,00,000	—	30,00,000
2	Governor and Council of Ministers	(Revenue)	2,70,10,000	88,96,000	3,59,06,000
3	Administration of Justice	(Revenue)	15,98,53,203	2,61,45,000	18,59,98,203
		(Capital)	12,99,98,000	—	12,99,98,000
4	General Administration	(Revenue)	19,52,85,900	2,51,73,000	22,04,58,900
		(Capital)	1,84,17,000	—	1,84,17,000
5	Land Revenue and District Administration	(Revenue)	1,06,02,67,000	2,44,000	1,06,05,11,000
6	Excise and Taxation	(Revenue)	9,23,25,000	—	9,23,25,000
7	Police and Allied Organisations	(Revenue)	91,33,39,868	7,79,517	91,41,19,385
		(Capital)	68,03,000	—	68,03,000
8	Education	(Revenue)	2,79,57,66,277	—	2,79,57,66,277
		(Capital)	94,57,03,000	—	94,57,03,000
9	Health and Family Welfare	(Revenue)	1,62,29,78,500	4,96,284	1,62,34,74,784
		(Capital)	1,25,62,01,000	—	1,25,62,01,000
10	Public Works—Roads, Bridges and Buildings	(Revenue)	1,55,70,32,000	7,94,585	1,55,78,26,585
		(Capital)	1,35,41,63,000	18,14,26,586	1,53,55,89,586
11	Agriculture	(Revenue)	31,72,14,296	—	31,72,14,296
12	Horticulture	(Revenue)	46,26,72,828	—	46,26,72,828
		(Capital)	12,00,00,000	—	12,00,00,000

1	2		3	4	5
13	Irrigation, Water Supply and Sanitation	(Revenue)	1,77,80,67,515	—	1,77,80,67,515
		(Capital)	77,94,52,000	—	77,94,52,000
14	Animal Husbandry, Dairy Development and Fisheries	(Revenue)	20,000	—	20,000
		(Capital)	39,98,000	—	39,98,000
15	Planning and Backward Area Sub-Plan	(Revenue)	21,85,87,000	—	21,85,87,000
		(Capital)	66,47,50,000	—	66,47,50,000
16	Forest and Wild Life	(Revenue)	18,81,96,000	21,83,741	19,03,79,741
		(Capital)	33,15,000	—	33,15,000
17	Election	(Revenue)	23,86,58,752	—	23,86,58,752
18	Industries, Minerals, Supplies & Information Technology	(Revenue)	2,44,39,810	—	2,44,39,810
		(Capital)	44,45,000	—	44,45,000
19	Social Justice and Empowerment	(Revenue)	1,00,87,02,493	—	1,00,87,02,493
		(Capital)	1,00,00,000	—	1,00,00,000
20	Rural Development	(Revenue)	31,88,14,000	24,41,000	32,12,55,000
		(Capital)	26,17,000	—	26,17,000
21	Co-operation	(Revenue)	1,94,45,239	—	1,94,45,239
		(Capital)	56,32,51,200	—	56,32,51,200
22	Food and Civil Supplies	(Revenue)	55,15,29,983	—	55,15,29,983
23	Power Development	(Revenue)	2,72,31,628	—	2,72,31,628
		(Capital)	2,29,85,28,000	—	2,29,85,28,000
24	Printing and Stationery	(Revenue)	5,22,92,974	—	5,22,92,974
25	Road and Water Transport	(Revenue)	91,17,72,753	—	91,17,72,753
		(Capital)	5,90,00,000	—	5,90,00,000
26	Tourism and Civil Aviation	(Revenue)	50,21,39,500	—	50,21,39,500
		(Capital)	1,55,79,000	—	1,55,79,000
27	Labour, Employment and Training	(Revenue)	9,29,17,516	—	9,29,17,516
		(Capital)	2,65,00,000	—	2,65,00,000

1	2		3	4	5
28	Urban Development, Town and Country Planning and Housing	(Revenue)	15,10,54,000	—	15,10,54,000
		(Capital)	7,50,00,000	—	7,50,00,000
29	Finance	(Revenue)	33,62,91,817	3,17,42,38,000	3,51,05,29,817
		(Capital)	3,000	3,95,28,60,000	3,95,28,63,000
30	Miscellaneous General Services	(Revenue)	18,38,91,000	2,53,61,334	20,92,52,334
		(Capital)	4,71,41,000	—	4,71,41,000
31	Tribal Development	(Revenue)	41,50,68,900	45,12,000	41,95,80,900
		(Capital)	38,89,03,000	—	38,89,03,000
32	Scheduled Castes Sub-Plan	(Revenue)	33,82,33,111	—	33,82,33,111
		(Capital)	48,69,57,000	—	48,69,57,000
	Total	**(Revenue)**	**16,60,32,92,949**	**3,27,34,30,461**	**19,87,67,23,410**
		(Capital)	**9,26,37,24,200**	**4,13,42,86,586**	**13,39,80,10,786**
		Grand Total	**25,86,70,17,149**	**7,40,77,17,047**	**33,27,47,34,196**

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

This Bill is introduced in pursuance of clause (1) of article 204 read with article 205 of the Constitution of India to provide for the appropriation from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh of the moneys further required to meet the expenditure charged on the Consolidated Fund and other expenditure as voted by the Legislative Assembly in respect of the estimated expenditure of the Government of Himachal Pradesh for the financial year 2017-2018.

(JAI RAM THAKUR)
Chief Minister.

SHIMLA :
The 7th March, 2018.

RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSTITUTION OF INDIA

[Finance Department File No. Fin-A-C (6)-2/2017]

The Governor, Himachal Pradesh, having been informed of the subject matter of the Himachal Pradesh Appropriation Bill, 2018, recommends, under article 207 of the Constitution of India, the introduction in and consideration by the Legislative Assembly of the said Bill.

THE HIMACHAL PRADESH APPROPRIATION BILL, 2018

A

BILL

to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh for the services for the financial year ending on 31st day of March, 2018.

(JAI RAM THAKUR)
Chief Minister.

(YASHWANT SINGH CHOGAL)
Secretary (Law).

SHIMLA :
The 7th March, 2018.

राजकीय मुद्रणालय, हि0 प्र0, शिमला—2388–वित्त / 2018—4–3–2018—250 प्रतियां।